

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

राज ठाकरे और बीजेपी में ठनी... भाजपा ने अमित ठाकरे को दी चेतावनी!

महाराष्ट्र के पालघर में आदिवासी महिला का बलात्कार... आरोपी तीन साल से कर रहा था रेप

मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत में पिछले दिनों उठा भूचाल शांत होने था कि अब राज ठाकरे और बीजेपी में ठन्ते हुए दिख रहा है। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चेतावनी दे डाली है। दरअसल राज ठाकरे के बेटे को एक टोल नाके पर कुछ मिनट इंतजार करना पड़ा था, जिस कारण उनके कार्यकर्ताओं ने टोक नाके पर जमकर उत्पात मचाया था।



इसी टोल नाके विवाद पर अब बीजेपी ने वीडियो जारी कर अमित को चेतावनी दी। टोल नाका विवाद में महाराष्ट्र बीजेपी ने वीडियो जारी कर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में दादागिरी सहन नहीं करेगी।

इसी कमी के कारण करीब 3 से साढ़े 3 मिनट तक टोल नाके पर रुकना पड़ा था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला की 10 मिनट तक गाड़ी को रोका गया और उनके साथ बदतमीजी की गई। वीडियो में आगे कहा गया कि अमित की गाड़ी को रोका इसलिए मनसे कार्यकर्ताओं ने टोल नाका तोड़ दिया। जब इस बारे में अमित को पूछा गया तो वो अपना राक्षसी आनंद छिपा नहीं पाए।

इस कारण रोकी जा रही थीं गाड़ियां
वीडियो में कहा गया है कि, फास्ट टैग में कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से गाड़ियों को रोका जा रहा था। अमित ठाकरे की गाड़ी को भी

बीजेपी ने वीडियो में कहा कि याद रखना ये जनता की सरकार की है। किसी एक नेता या उसके बेटे के लिए

नियम बदले नहीं जाएंगे। अगर ऐसा किया गया तो ईमानदारी से टोल भरने वाले हर व्यक्ति की प्रताड़ना होगी जो हमें मंजूर नहीं है। अमित आपने कहा कि पिता की वजह से पहले 65 टोल

क्या था मामला...

बता दें कि अमित ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे से शिरडी की ओर जा रहे थे। उनकी कार रात 9 बजे के करीब सिन्नर के गोडे टोल प्लाजा पर पहुंची। यहां टोल पर फास्टैग ब्लैकलिस्टेड होने के कारण बैरियर नहीं खुला था। जिसके बाद टोल पर आधे घंटे रोकने का आरोप लगाते हुए मनसे के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जबकि टोलप्लाजा कर्मियों ने मामला सुलझते ही अमित की कार को 3 मिनट में भेज दिया गया था। वहीं, इस बारे में अमित ने अपनी सफाई में कहा था कि टोल प्लाजा कर्मचारियों ने मुझे (अमित ठाकरे को) इंतजार करवाते हुए दुर्व्यवहार किया।

नाके बंद हो गए और अब मेरी वजह से एक टोल नाका और बंद हो गया। अमित इस तोड़फोड़ के बाद भी वो टोल नाका बंद नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में दादागिरी नहीं चलने देंगे।



पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में 29-वर्षीय एक आदिवासी महिला के साथ उसके नियोक्ता ने कथित तौर पर बार-बार बलात्कार किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दहानू पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी खेत का मालिक है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खेत में महिला 2021 से काम कर रही थी और आरोपी तीन वर्षों से कथित तौर पर महिला का बार-बार बलात्कार कर रहा था तथा महिला को डरा-धमका भी रहा था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है।

तीन साल में 7092 किसानों ने की खुदकुशी

खराब मौसम से किसान उलझे कर्ज के जाल में...

मुंबई : विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 के बीच अमरावती, नागपुर और औरंगाबाद विभागों में कुल 7092 किसानों ने आत्महत्या की है। कुणाल पाटिल, सुलभा खोडके सहित अन्य सदस्यों के सवाल के जवाब में मदद और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने माना कि लगातार हो रही बेमौसम बारिश, ओला



वृष्टि और अपर्याप्त बारिश की वजह से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और किसान दिन-प्रतिदिन कर्ज के जाल में उलझे रहे हैं।

मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा कि राज्य में पिछले 3 साल अर्थात 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 के बीच अमरावती विभाग में 3452, नागपुर विभाग में 957 तथा मराठवाडा विभाग में 2683 किसानों की आत्महत्या पंजीकृत की गई है। आत्महत्याओं की जांच में पाया गया कि लगातार अपर्याप्त, कर्ज बाजारी सहित कर्ज के ताकदे की वजह से अमरावती में 1404, नागपुर में 317 तथा मराठवाडा में 2110 किसानों ने खुदकुशी की है। मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि कम कृषि, शाश्वत सिंचन का अभाव, बदलते मौसम, निवेश और श्रम की तुलना में कृषि आय नहीं मिलने, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य नहीं मिलने, कर्ज के जाल में उलझने की वजह से किसान आर्थिक दिक्कतों में फंस गए हैं।

तत्कालीन विभागीय आयुक्त औरंगाबाद की रिपोर्ट खारिज...!

पाटिल ने लिखित उत्तर में कहा कि विभागीय आयुक्त औरंगाबाद ने मदद और पुनर्वास विभाग को 30 जून 2023 को भेजी रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कई योजनाएं बंद कर खरीफ और रबी मौसम में प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन विभागीय आयुक्त औरंगाबाद के तेलगाना की तर्ज पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देना संभव नहीं है। केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की तरह से नमो किसान महासम्मान योजना के तहत हर साल 6 हजार रुपए देने के लिए 6060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

एकनाथ खडसे के दामाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत...

दो साल से अधिक समय बिताया जेल में

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी 2016 के जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी के दो साल से अधिक समय बाद मंगलवार को जेल से बाहर आये। उन्हें उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली है। चौधरी के वकील मोहन टेकावड़े ने बताया कि एक लाख रुपये की जमानत राशि का भुगतान करने समेत सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके मुवकिल को मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से छोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय ने 21 जुलाई



को उन्हें जमानत दी थी, लेकिन यहां विशेष पीएमएलए अदालत में जमानत औपचारिकताएं मंगलवार को ही पूरी हो पायीं, उसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। शीर्ष अदालत के निर्देश पर विशेष पीएमएलए अदालत

के न्यायाधीश ने चौधरी की रिहाई के लिए कुछ शर्तें लगायीं, जिनमें उन्हें धनशोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को अपना पासपोर्ट सौंपना है। जमानत की शर्तों के अनुसार चौधरी को हर महीने के पहले शुक्रवार को ईडी कार्यालय में पेश होने तथा विशेष अदालत (मुंबई) की अनुमति के बगैर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने को कहा गया है। विशेष अदालत ने कहा कि सुनवाई के शीघ्र निस्तारण के लिए चौधरी को अदालत की हर सुनवाई में आना होगा तथा जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना होगा।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

मुकदमेबाज सरकार

यह तथ्य चकित करने वाला है कि 6.3 लाख मुकदमों में पक्षकार केंद्र सरकार है। जब केंद्र सरकार इतने अधिक मुकदमे लड़ रही है तो फिर यह सहज ही समझा जा सकता है कि राज्य सरकारें भी बड़ी संख्या में मुकदमे लड़ रही होंगी। वास्तव में इस एक कारण से भी

निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक हालिया आंकड़े के अनुसार हर तरह के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या पांच करोड़ से अधिक पहुंच गई है। यह आंकड़ा यह भी बताता है कि लंबित मुकदमों की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है—न केवल निचली अदालतों में, बल्कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी। निचली अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। पांच साल पहले निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 2.9 करोड़ थी। अब उनकी संख्या 4.4 करोड़ पहुंच गई है। यह स्थिति गहन चिंता का विषय बननी चाहिए, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था चरमरा रही है। निःसंदेह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी स्थिति संतोषजनक नहीं, क्योंकि वहां भी लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण न्यायाधीशों और संसाधनों की कमी बताई जाती है। निःसंदेह यह एक कारण है, लेकिन इसे एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ते चले जाने का एक और प्रमुख कारण है तारीख पर तारीख का सिलसिला। न जाने कितने मामले ऐसे हैं, जिनका निस्तारण दो-चार वर्ष में हो जाना चाहिए, पर वे दशकों तक लटक रहे हैं। यही स्थिति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी है। पांच करोड़ मुकदमे लंबित रहने का मतलब है कि इससे कहीं ज्यादा लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं, क्योंकि कई मामलों में एक से अधिक लोग अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे होते हैं। यह एक तरह से न्यायिक व्यवस्था की ओर से किया जाना वाला उत्पीड़न है। खेद की बात यह है कि इस उत्पीड़न में सरकारें भी शामिल हैं।

क्या इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो सकता है कि सरकारें अपने ही लोगों को मुकदमेबाजी में उलझाए रहें? लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से केवल लोगों का न्यायिक तंत्र पर भरोसा ही कमजोर नहीं होता, बल्कि देश की प्रगति भी बाधित होती है, क्योंकि करोड़ों लोग काम-धंधे पर ध्यान देने के बजाय अदालतों के चक्कर लगाते हैं और अपने समय के साथ धन की भी बबार्दी करते हैं। नीति-नियंत्रणों की ओर से इस तरह की जो बातें रह-रहकर की जाती हैं कि लंबित मुकदमे एक बड़ी समस्या हैं और न्याय में देरी अन्याय है, उनसे देश की जनता आजिज आ चुकी है, क्योंकि तमाम चिंता जताए जाने के बाद भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। आखिर उस चिंता का क्या मूल्य-महत्व, जो समस्या के समाधान में सहायक न बने?

+91 99877 75650

editor@rokhoklehaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मुंबई के मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे इतने सारे पत्थर क्यों हैं ?

सपनों के शहर कहे जाने वाले मुंबई के मरीन ड्राइव का नजारा बेहद शानदार होता है। अगर कोई मुंबई जाए और मरीन ड्राइव का जिक्र न करे, ऐसा शायद ही हो। लोग मरीन ड्राइव पर आते हैं। यहां आकर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें यह शांति का एहसास होता है। यहां पड़ी चट्टानों से टकराती हुई पानी की लहरों की आवाज हर किसी को अच्छी लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरीन ड्राइव पर पड़े ये एक जैसे इतने सारे पत्थर कहां से आए? क्या ये प्राकृतिक हैं या फिर इंसानों ने इन्हें बनाया है? अगर इंसानों ने बनाया है तो फिर ये वहां क्यों पड़े हैं? आइए जानते हैं।



मरीन ड्राइव

मुंबई में मरीन ड्राइव का निर्माण 1920 के आसपास हुआ था। मरीन ड्राइव के शानदार घुमाव पर लगी स्ट्रीट-लाइटें जब रात में जलती हैं तो नजारा वाकई देखने वाला होता है, इसलिए इसे क्वीन्स नैकलेस के नाम से भी जाना जाता है। रात में ऊंची इमारतों से देखने पर मरीन ड्राइव का नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है।

टेट्रापोड (पत्थर के जैसा बना हुआ)

जब भी कोई मरीन ड्राइव जाता है, उसकी इच्छा समुद्र तट पर पड़े टेट्रापोड पर बैठने की जरूर होती है। लोग इनपर सुकून की सांसे लेने के लिए या तस्वीरें खिंचवाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये टेट्रापोड प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि इन्हें इंसानों ने बनाया है और इनका निर्माण एक खास वजह से किया गया था।

क्या है इनका काम ?

इन्हे मजबूत और भयंकर लहरों से शहर की रक्षा करने लिए बनाया गया है। दरअसल, समुद्र की तेज लहरें जब तट से टकराती हैं तो दूर तक कंपन जाती हैं। ऐसे में समुद्र के किनारे पर ये टेट्रापोड कटाव और अन्य समस्याओं से शहर को बचाते हैं। इन्हे एक दूसरे से इंटरलॉक करके रखा गया है, ताकि हाईटाइट के समय ये लहर

के बहाव को कम कर सकें।

कितना है वजन

मुंबई के मरीन ड्राइव पर नब्बे के दशक में इन पत्थरों को लाया गया था। सबसे पहले टेट्रापोड का इस्तेमाल फ्रांस में किया गया था। इनका वजन 2 से लेकर 10 टन तक हो सकता है। ये अगर वहां न हों तो मुमकिन है कि समुद्र की तेज लहरें शहर के आसपास के क्षेत्र में आतंक मचा दें। ये लहरों के फोर्स को कम करते हैं।

पबजी खेलते हुए महिला से हुई दोस्ती... शख्स ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचा

मुंबई : पबजी इन दिनों भारत में काफी हाईलाइट हो रहा है। एक तरफ सीमा हैदर और सचिन की दोस्ती पबजी खेलते हुए हुई और सीमा हैदर सचिन के लिए भारत आ गई। वहीं एक मामला मुंबई से सामने आया है यहां एक शख्स ने पबजी खेलते हुए महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
वीडियो क्लिप सोशल मीडिया



पर जारी करने की दी धमकी
शिकायतकर्ता के अनुसार, व्यक्ति ने जनवरी 2023 तक विभिन्न होटलों में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और इस

आरोपी ने शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध...

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शख्स और पीड़िता ने मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में साथ काम भी किया था। आरोपी और महिला की मुलाकात 2020 के अंत में ऑनलाइन हुई थी और बाद में वह इवेंट मैनेजमेंट फर्म में काम करने लगी। आरोपी ने शादी का वादा करने के बाद महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

शख्स अपनी बात से मुकरा तो पुलिस में की शिकायत

अधिकारी ने कहा कि जब शख्स ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया तो महिला ने पुलिस से संपर्क किया और शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म के लिए सजा), 376 (एन) (2) (शादी करने का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कृत्य का वीडियो भी शूट किया। शिकायत के अनुसार महिला ने कहा कि शख्स ने उसको धमकी दी कि अगर उसने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो वह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी कर देगा।

अंधेरी ईस्ट चकला इलाके में भूस्खलन, मौके पर दमकल की चार गाड़ियां मौजूद



महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलजमाव, बाढ़ और भूस्खलन की समस्या देखी जा रही है। भारी बारिश के कारण मुंबई के अंधेरी ईस्ट से भी भूस्खलन की एक खबर सामने आ रही है। मुंबई अग्निशमन विभाग ने जानकारी दी है कि, महाराष्ट्र में रात करीब 2 बजे मुंबई के अंधेरी ईस्ट चकला इलाके में एक आवासीय सोसायटी के पास भूस्खलन की घटना हुई है। मौके पर दमकल की चार गाड़ियां और मुंबई पुलिस के जवान मौजूद हैं। वहीं, मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई के मेघवाड़ी इलाके में स्थित पीपुल्स वेलफेयर इंग्लिश हाई स्कूल की लैब की गैलरी आज सुबह करीब 6.45 बजे ढह गई।

मुंबई के अंधेरी में बीती रात हुई लैंडस्लाइड

एहतियातन बीएमसी ने खाली कराई बिल्डिंग इस दुर्घटना में बाल-बाल बचे इमारत के लोग...



मुंबई: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इशालवाड़ी में हुए लैंडस्लाइड की घटना के जखम अभी भरे भी नहीं थे कि लोनावला में मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड हुआ। जिसके बाद छह घंटे तक मलबा हटाने का काम चला और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इसके बाद अब मुंबई में भी ऐसा ही मामला पेश आया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में मंगलवार तड़के आठ मंजिला इमारत के पीछे मौजूद पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। जिसके कारण बीएमसी अधिकारियों ने इमारत से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इमारत को एहतियातन खाली कराया गया

बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि इमारत के पीछे स्थित पर्वतीय क्षेत्र से मिट्टी और चट्टानें गिरनीं। उन्होंने बताया कि रामबाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 168 कमरे हैं और भूस्खलन को देखते हुए इमारत को एहतियातन खाली करा लिया गया है। अधिकारी के अनुसार, पुलिस कर्मी, वार्ड कर्मी और दमकल विभाग को मौके पर भेजा गया है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर दमकल की दो गाड़ियां भेजी हैं।

उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस नियंत्रण कक्ष ने सोमवार देर रात करीब दो बजे अंधेरी (पूर्व) में महाकाली रोड पर स्थित रामबाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पीछे भूस्खलन के बारे में बीएमसी को सूचित किया।

शिंदे ही रहेंगे मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस विपक्ष मुख्यमंत्री को लेकर उड़ा रहा है पतंग... अजित पवार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री

मुंबई : पिछले कुछ दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री को बदलने की जोर शोर से चर्चा चल रही है। इस बीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और रहेंगे। शिंदे को बदलने की चर्चा को सिर से खारिज कर दिया।

देवेंद्र फडणवीस विधानभवन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और आगे भी वही रहेंगे अजित पवार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा चल रही है। ऐसी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जगह उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। हम उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। बिना नाम लिए अपने सहयोगी दल राकांपा

अजित पवार गुट को दो टूक सुनाते हुए कहा कि किसी भी पार्टी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री उसकी पार्टी का होगा। अगर ऐसे ही महायुति में शामिल सभी पार्टियां ऐसी हो सोचना शुरू कर देगी तो गठबंधन कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि कल भाजपा के लोग चाहते होंगे कि उनका मुख्यमंत्री बने, राकांपा के लोग चाहते होंगे कि अजित पवार मुख्यमंत्री बने। यह कार्यकर्ताओं की भावना है जो गलत नहीं है। लेकिन, मुख्यमंत्री पद पर कोई बदलाव नहीं होगा। यह मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार को इस बारे में पहले ही आगाह



कर दिया गया था और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि 10, 11 और 9 तारीख को कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो विस्तार होगा।

दस अगस्त तक राज्य के मुख्यमंत्री का बदलेगा चेहरा - पृथ्वीराज चव्हाण

पिछले कई दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री बदलेंगे ऐसी चर्चा शुरू है इस बीच चर्चा को उस समय हवा मिल गई जब सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा बयान दे दिया कि आगामी 10 अगस्त तक राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। चव्हाण विधानभवन में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महायुति में शामिल होने के पहले अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा ने आश्वासन दिया है इसलिए आने वाले दस अगस्त तक एकनाथ शिंदे की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री दिखेगा।

विपक्ष ने मुंबई पुलिस में 'संविदा के आधार पर पुलिसकर्मी' भर्ती करने पर चिंता जताई



मुंबई : महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने मुंबई पुलिस द्वारा 'संविदा के आधार' पर कर्मियों को रखने की योजना पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि यह 'जोखिम भरा' कदम बल के साथ-साथ लोगों के लिए हानिकारक होगा। विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह खतरनाक और जोखिम भरा है।" दानवे

ने दावा किया कि मुंबई पुलिस बल में संविदा पुलिसकर्मियों को शामिल करने से 'वैग्नर ग्रुप' जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दानवे रूस की निजी सेना 'वैग्नर ग्रुप' के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पिछले महीने किए गए विद्रोह का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा, "मैं पुलिस में संविदा के आधार पर भर्ती का विरोध करता हूँ। इससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। अगर 'पुलिस' सरकारी आदेशों का

पालन न करे तो क्या होगा? एक सुरक्षा गार्ड को संविदा पर रखा जा सकता है, लेकिन एक पुलिसकर्मी को संविदा पर नहीं रखा जा सकता है।" मुंबई पुलिस में कांस्टेबल की कमी को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम (एमएसएससी) से 3,000 कर्मियों को 'आउटसोर्स' करने की मंजूरी दे दी है। एमएसएससी राज्य पुलिस का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने सोमवार को इस आशय का एक आदेश जारी किया। उच्च सदन में, कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य भाई जगताप ने जानना चाहा कि गुंडों को 'संविदा पर रखे गए पुलिसकर्मियों' का क्या डर होगा? उन्होंने इस साल की शुरुआत में पुलिस भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं की स्थिति के बारे में भी सवाल किया।

आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण से ईओडब्ल्यू की पूछताछ फिर हो सकती है पूछताछ...

मुंबई : युवा सेना के सचिव और आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण से सोमवार को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों ने पूछताछ की। यह पूछताछ जंबो कोविड केयर सेंटर घोटाले से संबंधित थी। ईओडब्ल्यू अधिकारी ने बताया कि आज हमने चव्हाण का बयान लिया है, अगर जरूरत पड़ी तो चव्हाण को दोबारा बुलाया जा सकता है। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक चव्हाण को कोरोना महामारी के दौरान जंबो कोविड सेंटर घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने कुछ महीने पहले चव्हाण से पूछताछ की थी और उनके घर पर तलाशी भी ली थी। ईओडब्ल्यू के अधिकारी ने बताया कि इस मामले



में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी को कुछ दस्तावेज मिले थे और उनका मानना है कि ये दस्तावेज जांच में मददगार हो सकते हैं। इसलिए ईडी ने ये दस्तावेज ईओडब्ल्यू के साथ साझा किए हैं। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने दहिसर जंबो कोविड सेंटर के सुजीत पाटकर और डीन किशोर बिसुरे को गिरफ्तार किया है। पिछले साल अगस्त में लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के चार पार्टनर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें सुजीत मुकुंद पाटकर का नाम भी शामिल था। अक्टूबर 2022 में मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि एक ऐसी फर्म को कोविड सेंटर बनाने का ठेका दिया गया, जिसके पास स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का कोई अनुभव नहीं था। इस फर्म को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेका मिला था।

18.05 लाख रुपये के मादक पदार्थ जब्त, 2 नाइजीरियाई समेत 3 हुए गिरफ्तार



ठाणे : नवी मुंबई पुलिस ने छापों की दो कार्रवाई में 18.05 लाख रुपये के मादक पदार्थ जब्त किये हैं और इस मामले में दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ (एनसी) ने खारघर रेलवे स्टेशन के पास जाल बिछाया और 32 और 34 साल की उम्र के दो नाइजीरियाई व्यक्तियों को पकड़ लिया।

पुलिस ने एक विज्ञप्ति में

बताया कि नाइजीरियाई व्यक्तियों के पास से 4.40 लाख रुपये मूल्य की कुल 44 ग्राम मेथाक्वालोन बरामद की गई। विज्ञप्ति के मुताबिक एएनसी ने एक अन्य मामले में एपीएमसी थाना क्षेत्र में छापा मारा और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से 2.60 ग्राम एलएसडी नामक मादक द्रव्य जब्त किया गया।

बाजार में इसका मूल्य 13.65 लाख रुपये है। इसमें यह भी बताया गया है कि सोमवार को तीन व्यक्तियों के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को मादक पदार्थ कहाँ से मिले और वे इसे किसे बेचना चाहते थे।

दो महीने बाद शुरू होगा 556 शौचालय बनाने का काम

मनपा को मिल रहा निजी कंपनियों का साथ...

मुंबई : मनपा प्रशासन ने लॉट 12 के तहत मुंबई शहर में 556 शौचालय जिसमें 20 हजार ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया था। मनपा इन शौचालय को बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने के योजना बनाई थी। मनपा ने शौचालय बनाने के लिए टेंडर भी निकाल दिया था। इस बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई की जनता को उच्च कोटि का शौचालय उपलब्ध कराने के लिए निजी कंपनियों से मुलाकात की और उन्हें सी एस आर फंड के तहत मनपा को शौचालय उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। उनकी गुहार पर हिंदुस्तान लीवर

नहीं खर्च करना पड़ेगा मनपा की तिजोरी का पैसा



सहित कई अन्य नामचीन कंपनियों ने मुंबई के लोगों को उच्च कोटि का शौचालय उपलब्ध कराने के लिए आगे आई। पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा सोमवार को मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल से मिलकर शौचालय उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के बारे में जाना। मनपा आयुक्त चहल ने लोढ़ा को बताया कि लॉट 12 के तहत शौचालय बनाने का निकाला टेंडर अभी रद्द नहीं किया गया है। उन्होंने बताया की 556 शौचालय जिसमें 20 हजार से अधिक ब्लॉक तैयार किए जाएंगे

यह कार्य अगले दो महीने में शुरू किया जाएगा। मनपा प्रशासन ने मुंबई भर में शौचालय बनाने वाले स्थानों की सूची तैयार कर रही है। मनपा को हिंदुस्तान लीवर सहित कई अन्य कंपनियां शौचालय बनाकर देने की तैयारी दिखाई है। एक शौचालय के

बनाने पर लगभग 3 करोड़ खर्च होगा जिसका वहन निजी कंपनियों करेगी। यह शौचालय बाहर से बन कर आएगा जिससे शौचालय लगाने के स्थान तक गाड़िया कैसे पहुंचेगी यह देखा जा रहा है। मनपा आयुक्त ने कहा कि इसी लिए अभी तक निविदा रद्द नहीं किया है। जहा आप बना हुआ शौचालय लगाना मुमकिन नहीं होगा वहा पर शौचालय बनाया जाएगा जिसके लिए निकाली गई निविदा में ठेकेदार को काम देकर शौचालय बनाया जाएगा।

25 स्थानों पर आपला दवाखाना भी खुलना है बाकी...

लोगो को घर के पास ईलाज की सुविधा मिले इसके लिए मनपा ने हिंदू हृदय सम्राट दवाखाना की शुरुआत की है। मनपा प्रशासन ने 164 स्थानों पर यह दवाखाना शुरू भी कर दिया है लेकिन 25 स्थानों पर जहा पर लोगो की मांग है अभी तक दवाखाना नहीं खुल पाया है। मनपा आयुक्त चहल ने जगह संबंधी समस्या की जानकारी देते हुए इन स्थानों पर जल्द दवाखाना शुरू करने की गवाही दी।

गृहनिर्माण मंत्री सावे की बड़ी घोषणा झोपड़पट्टी के पहली मंजिल पर रहने वाले नागरिकों को मिलेगा घर

विधान परिषद में प्रवीण दरेकर सहित अन्य सदस्यों ने उठाया था मुद्दा

मुंबई : गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे ने सोमवार को झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है। विधानपरिषद में मंत्री सावे ने कहा कि झोपड़पट्टी में पहली मंजिल पर रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दी जाएगी। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने झोपड़पट्टी में पहली मंजिल पर रहने वाले नागरिकों को मुफ्त घर देने का मुद्दा उपस्थित किया था इसके लिखित जवाब सावे बोल रहे थे। गृहनिर्माण मंत्री ने कहा कि झोपड़पट्टी के पहली मंजिल पर रहने वाले नागरिकों को झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के



संबंध में अंतिम मंजूरी के लिए झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण से एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार को सौंपने का अनुरोध किया गया है। मंत्री अतुल सावे ने कहा कि झोपड़पट्टी की पहली मंजिल पर अवैध तरीके से रहने वाले नागरिकों के मुफ्त घर मिलने को लेकर सरकार के पास कोई कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री सावे ने कहा कि मुंबई सहित ठाणे सहित अन्य जिलों में बड़ी संख्या में झोपड़पट्टी है जिसमें पहली मंजिल पर लोग रहते हैं इस योजना के शुरू होने के बाद लाखों नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस चर्चा में भाई गिरकर, रमेश पाटिल, उमा खापरे सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया।

तहत घर दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। गृहनिर्माण मंत्री ने कहा कि साल 1976 के पहले बने झोपड़पट्टी के पहली मंजिल पर रहने वाले निवासियों को स्लम पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास फ्लैट का लाभ देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस

मशीन वितरण प्रोग्राम पर खर्च हुए 2 करोड़...



मुंबई : मनपा प्रशासन सिलाई मशीन, घर घंटी और मसाला पीसने की मशीन के वितरण प्रोग्राम पर लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। जबकि अभी तक इस तरह के प्रोग्राम नगरसेवक अपने वार्ड में अपने स्तर पर करते थे और गरीब परिवार को उसका फायदा मिल जाता था। इस बार मनपा में नगरसेवक नहीं होने से राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम किया जिसकी भव्यता काफी थी। मनपा ने इस प्रोग्राम के आयोजन पर पैसे खर्च किए जिसकी जानकारी आरटीआई से सामने आई है। एफ नार्थ वार्ड ने प्रोग्राम के आयोजन

पर हुए खर्च का विवरण दिया है। बता दे कि चूनाभट्टी स्थित सोमैया मैदान 13 मई 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गरीब महिलाओं को उनके स्वबल पर खड़ा होने के लिए मनपा ने सिलाई मशीन, घर घंटी और मसाला पीसने की मशीन आदि का वितरण किया। मनपा प्रशासन हर साल नियोजन विभाग की ओर से इस तरह गरीब महिलाओं को उन्हें उनके पैर पर खड़ा होने के लिए और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिलाई मशीन घर घंटी सहित अन्य साहित्य उपलब्ध कराती रहती है।

महिलाएं स्वावलंबी बनें, उनका विकास हो, उनका जीवन स्तर उंचा उठे, विकास कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए मनपा द्वारा जेंडर बजट के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें योजना के मापदंडों के अनुरूप अर्हता प्राप्त करने वाली महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मशीनरी खरीदने के लिए नगर पालिका द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस साल मनपा में किसी की सरकार नहीं होने के कारण मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल जो कि प्रशासक के रूप में काम काज देख रहे हैं गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए मनपा द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बुलाया। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई मनपा से सिलाई मशीन, घर घंटी और मसाला पीसने की मशीन वितरण कार्यक्रम पर हुए खर्च की जानकारी मांगी थी।

मिड डे मील योजना में घोटाले की होगी जांच... कामगार मंत्री सुरेश खाडे की घोषणा



मुंबई : निर्माण कार्य मजदूरों की मध्याह्न भोजन योजना सहित अन्य सामग्री देने में हुई घोटाले की कामगार आयुक्त के मार्फत जांच की जाएगी। विधानसभा में इस बात की घोषणा कामगार मंत्री सुरेश खाडे ने की। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कैलास घाडगे पाटिल ने धाराशिव में मजदूरों की मध्याह्न भोजन योजना में हुए घोटाले का मामला उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि धाराशिव जिले में निर्माण कार्य मजदूरों की मध्याह्न भोजन योजना में तकरीबन 28 हजार मजदूरों के सद्देहास्पद पंजीकरण कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। यह बात जिला

अधिकारी की तरफ से नियुक्त जांच समिति सामने आई है, क्या यह बात सही है? हालांकि कामगार मंत्री ने इस बात को गलत बताया। मंत्री ने कहा कि ये सही है कि इस मामले की जांच के लिए समिति बनाई थी, लेकिन उसमें कामगार अधिकारी को शामिल नहीं किया गया। केवल पंजीकृत मजदूरों के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना काल में इस योजना में गैर पंजीकृत मजदूरों को भी शामिल किया गया।

कामगार मंत्री ने कहा कि 10 अक्टूबर 2022 तक पंजीकृत मजदूरों की संख्या 15 लाख 30 हजार थी जो आज बढ़कर 26 लाख 38 हजार हो गई है। खाडे ने कहा कि मेरे कार्यकाल में 11 लाख से अधिक मजदूरों का पंजीकरण हुआ है। अब सिर्फ पंजीकृत मजदूरों को ही मध्याह्न भोजन दिया जाएगा।

मनपा के सामने 95 अति धोकादायक इमारत खाली कराने का आह्वान

मुंबई। रहवासियों को घर मिलने की गारंटी और वैकल्पिक व्यवस्था भी देने तैयार मुंबई मनपा प्रशासन ने बेहद खतरनाक स्थिति वाली 95 इमारतों के रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने घोषणा की है कि इन इमारतों में रहने वाले रहवासियों को नई इमारत बनने पर उन्हें अवश्य घर मिलेगा और वह रहवासियों के अस्थायी वैकल्पिक आश्रय प्रदान करने की भी गारंटी ले रहे हैं।

बता दे कि हर साल की तरह मनपा प्रशासन इस साल भी मानसून पूर्व मुंबई में 226 इमारतों के जर्जर होने की घोषणा की थी। कुछ साल पहले मुंबई में खतरनाक और जर्जर इमारतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मानसून के दौरान जर्जर इमारत गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या भी अधिक होती थी। मनपा प्रशासन ने कुछ साल पहले खतरनाक



इमारतों को गिराने की सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई मनपा नियमानुसार 30 साल से अधिक पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। जो इमारत जर्जर पाई जाती है उन्हें खाली करने के लिए 354 नोटिस जारी किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट में डबड़िया होने पर इमारत के रहवासी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। मनपा द्वारा नियुक्त टैग कमेटी के पास भी रहवासी शिकायत करते हैं। मनपा प्रशासन जर्जर हुई इमारतों जिन्हे कोर्ट ने भी किसी तरह का कोई स्टे आदि नहीं दिया है ऐसे इमारतों में रह रहे रहवासियों को तत्काल घर

गारंटी ले रही है। मनपा आयुक्त का कहना है कि खतरनाक इमारत में रहकर अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मनपा द्वारा घोषित 226 जर्जर इमारतों में से 35 शहर में हैं, 65 पूर्व उपनगर में और 126 पश्चिमी उपनगर में हैं। जिनमे से 110 इमारतों का मामला कोर्ट में है। जबकि 9 इमारतों का मामला मनपा के टैग कमेटी के पास है। मनपा प्रशासन ने बताया 95 इमारतों को मानसून से पहले खाली कराकर गिराने का निर्णय लिया था। अतिक्रमण उन्मूलन विभाग की ओर से कार्रवाई की जानी थी। लेकिन अक्सर यहां के निवासी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसलिए मनपा आयुक्त ने इन निवासियों से घर खाली करने की अपील की है। मनपा आयुक्त ने कोर्ट में प्रलंबित इमारतों के रहवासियों को इमारत न तोड़ने की गारंटी।

मुंबई/ 988 साल पुराने परेल वर्कशॉप के पुनर्विकास का विरोध

मुंबई : परेल ट्रेन टर्मिनस बनाने के लिए 988 साल पुराने परेल वर्कशॉप को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर रेल यूनियन ने प्रशासन को नोटिस भेजा है। नोटिस में यूनियन ने मुंबई की सबसे पुराने रेल वर्कशॉप में से एक को खाली करने की आवश्यकता का विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि रेल विभाग के इस कदम से लगभग 1,000 पेड़ भी काटे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ 100 साल पुराने भी हैं। सेंट्रल रेल मजदूर संघ (सीआरएमएस) ने अन्य रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर परेल टर्मिनस के निर्माण के विरोध में भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया है। यूनियन के अनुसार, इससे शहर में भीड़ बढ़ जाएगी और सेंट्रल रेल अस्थिर हो जाएगी। परेल वर्कशॉप को बंद करने की वजह 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया टर्मिनस बनाना बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, वर्कशॉप के अंदर और परिसर में बहुत सारे पेड़ हैं।

मोबाइल लेकर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर



मुंबई : सायन पुलिस ने महिला से पहचान का फायदा उठाकर उसका मोबाइल प्राप्तकर अकाउंट से पैसे निकालकर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। शिकायतकर्ता महिला का बेटा सायन अस्पताल में पिछले कई दिनों से भर्ती है। जिसका ध्यान रखने के लिए महिला अस्पताल में रहती थी। वहीं रहनेवाले दूसरे परिवार के लोगों से उसकी मुलाकात हुई। उसपर भरोसा बन गया, इसबीच महिला ने फोन बार बतकरने के लिए उसे अपना मोबाइल दिया। आरोपी ने इसीके फायदा उठाकर महिला के युपीआई अकाउंट से पैसे निकाल लिए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला तब सामने आया जब उसे दवाई लेने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी और वह पैसे निकालने के लिए एटीएम में गई। जब अकाउंट से पैसे नहीं निकले तब मिनी स्टेटमेंट में अकाउंट से पैसे ट्रांजिक्शन किये जाने की जानकारी मिली। इसके बाद सारी घटना महिला ने अपने भाई को बताई और फिर महिला की शिकायत पर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में आरोपी के फरार होने की जानकारी पुलिस को मिली है। एफएआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है।

मोबाइल अपने पास ही रखा आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला बीमार थी तभी उसने फोन पर बात करवाया और महिला का मोबाइल अपने पास ही रख लिया। डॉक्टर ने सलाइन और इंजेक्शन लाने के लिए कहा। महिला ने पटोले को वह लेने के लिए भेजा। पटोले जो वहां से गया वहां से लौटा ही नहीं। पटोले के रिश्तेदार ने भी उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और फिर महिला के मोबाइल पर भी फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। तभी उसने मामले की शिकायत सायन पुलिस थाने में कई।

युपीआई से पैसे किये ट्रांसफर...

आरोपी को महिला के युपीआई आईडी का पासवर्ड पता चल गया था। इसलिए वह मोबाइल लेकर गया और युपीआई आईडी से ट्रांजिक्शन कर लिए। इसके बाद जब काफी समय तक वह नहीं लौटा तब उसे देखने से लोग बाहर गए। महिला के पास एटीएम कार्ड था जिससे पैसे निकालने वह एटीएम सेंटर में गई। जहां पहले उसने 10 हजार रुपये निकालने की कोशिश की नहीं निकली। फिर उसने 4 हजार निकले तो अकाउंट से निकल गया। इसके बाद मिनी स्टेटमेंट निकालने पर खुलासा हो गया।

अस्पताल में हुई पहचान
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने बताया है कि उसकी पहचान बेटे के बगल में इलाज ले रही एक युवती के परिवार वालों से हुई। जिसका रिश्तेदार रोहित पटोले है। पटोले कई दिनों से वहीं पर मौजूद था इसलिए महिला से अच्छी पहचान हो गई। एक दिन महिला बीमार हो गई उसे चक्कर आने लगा। तब आरोपी ने उसे सायन अस्पताल में इलाज करवाया। इसी दौरान उसे भाई को फोन लगाने के लिए महिला ने फोन दिया। इसी दौरान आरोपी ने मोबाइल का पासवर्ड देख लिया और मोबाइल भी आपसे पास रख लिया।

बेस्ट बसों में टपकता पानी परेशान यात्रियों के शिकायतों की बारिश!



मुंबई: यात्रियों को सुविधा देने वाली और मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन के नाम से जानी जाने वाली बेस्ट बसों में सफर करना मुंबईकरों को मुश्किल हो रहा है। बारिश के कारण बेस्ट की कई बसों से पानी का लीकेज हो रहा है। जिससे यात्री परेशान हो उठे हैं। यात्रियों को परेशानी भरी यात्रा करनी पड़ रही है।

यात्रियों ने इसकी शिकायत बेस्ट प्रशासन के पास की है और पूछ रहे हैं कि बसों में टपकता बारिश का पानी कब बंद होगा। उल्लेखनीय है बेस्ट मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन कही जाती है। बेस्ट उपक्रम 100 वर्षों से मुंबई वासियों को उनकी सेवा में मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही है। बेस्ट

के पास अब खुद की 1646 बसें हैं जबकि बेस्ट प्रशासन ने यात्रियों को सुविधा देने के लिए 1584 बस भाड़े पर ली है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। मुंबई के नागरिक सड़क पर बने गड्ढे से पहले ही परेशान है अब बेस्ट की बसों में पानी टपकने से और बुरा हाल हो रहा है। बेस्ट की बसों में पानी टपकने की घटना बेस्ट की वातानुकूलित बस और सामान्य बस दोनों में हो रहा है। खासकर बारिश के दौरान सीटों पर पानी टपकने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्रियों ने बेस्ट प्रशासन के पास बस में पानी टपकने की शिकायत की है और बसों में होने वाले लीकेज बंद करने की मांग की है।

निधि वितरण मामले को लेकर हंगामा... विपक्ष का आरोप, सरकार कर रही भेदभाव!

मुंबई : विधायकों को निधि वितरण का मामला सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदन में गूंजा। विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने यह मामला उठाते हुए कहा कि असमान निधि वितरण का मतलब जनता और जन प्रतिनिधियों पर अन्याय है। जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने विपक्ष के विधायकों को एक रुपए की निधि नहीं दी थी। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जन प्रतिनिधियों को आवश्यकता

**अन्याय दूर नहीं हुआ तो जाएंगे कोर्ट- थोरात
आवश्यकता अनुसार दी जाती है निधि: फडणवीस**

65 फीसदी निधि सत्ताधारी 100 विधायकों को निधि वितरण की सूची दिखाते हुए थोरात ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के 105 विधायक हैं, इनमें से कई भाजपा विधायकों को बहुत कम निधि मिली है। यह असंतुलन ठीक नहीं है। हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े निकाले हैं, जिन्हें ज्यादा निधि मिली है, उनके बारे में हमारे दिल में कोई पूर्वाग्रह की भावना नहीं है, इसलिए मैं सदन में उनके नामों का खुलासा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने 65 फीसदी निधि सत्ता में शामिल 100 विधायकों को दी है। मैं इस संबंध में केवल आंकड़े बताऊंगा, 742 करोड़, 580 करोड़, 482 करोड़, 456 करोड़, 436 करोड़, 392 करोड़ सभी राशियां सैकड़ों करोड़ में है।

के अनुसार निधि दी जाती है। इधर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात ने कहा कि असमान निधि वितरण से विधायकों और जनता में असंतोष पैदा हुआ है और सरकार ने यदि अन्याय दूर नहीं किया तो हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को दो



टूक सुनाते हुए कहा कि राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में तत्कालीन विपक्ष के विधायकों को एक रुपए की विकास निधि दी गई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने निधि वितरण मामले में भाजपा और उसके सहयोगी दल के विधायकों के साथ भेदभाव किया गया था, लेकिन हमने विपक्ष में रहते हुए कुछ नहीं बोला।

अब जबकि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया है और भाजपा-शिवसेना की सरकार आ गई है तो विपक्ष निधि वितरण मामले में सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए लोकप्रतिनिधि को आवश्यकता अनुसार निधि दी जाती है। मैं सदन के सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ

कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का बजट तैयार करते समय प्रत्येक विभाग से प्रस्ताव मंगाए जाते हैं, उसके आधार पर आर्थिक नियम समिति की बैठक लेकर उपलब्ध निधि पर विचार-विमर्श कर बजट तैयार करती है। फडणवीस ने कहा कि यह सही है कि पिछली सरकार द्वारा योजनाओं को बांटी गई निधि स्थगित कर दी गई। प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यों पर लगी रोक हटाई गई है। इस चर्चा में भाई जगताप, अनिल परब सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया।

बाला साहेब थोरात की सरकार को चेतावनी

कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात ने विधानसभा में आरोप लगाया कि सरकार ने 41 हजार करोड़ रुपए की पूरक मांग पेश की है, वह विधायकों को फोड़ने और फूटे गए विधायकों को संभालने के लिए है, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता, उन्हें भरपूर निधि की खैरत बांटी गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे विधायकों और जनता में असंतोष पैदा हुआ है और सरकार ने यदि अन्याय दूर नहीं किया तो हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

निधि आवंटन का असंतुलन,

महाराष्ट्र की राजनीति को बर्बाद कर रहा है...

मुंबई : राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद निधि का वितरण किया। इस वितरण में उन पर भेदभाव का आरोप है। एनसीपी से टूटकर उनके साथ आए विधायकों को उन्होंने भरपूर निधि दी है, इसे लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के नेता व सांसद संजय राऊत ने शिंदे सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा, 'अपने साथ आए विधायकों को निधि बांटना लूटमार कहलाता है क्योंकि मेरे हाथ में तिजोरी है इसलिए मैं लूट रहा हूँ।' निधि वितरण के इस असंतुलन से महाराष्ट्र की राजनीति बर्बाद हो गई है। अजीत पवार महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान वित्त



मंत्री थे और वर्तमान सरकार में भी वित्त मंत्री हैं। तब भी वही बातें हुई थीं। 'मेरे साथ ४० विधायक हैं इसलिए मैं निधि आवंटन से उनकी जेबें भरूंगा।' यह निधि आवंटन का असंतुलन है। यह महाराष्ट्र की राजनीति को बर्बाद कर रहा है। ऐसी टिप्पणी राऊत ने की। 'रवींद्र वायकर इस मामले में अदालत गए हैं। निधि आवंटन का यह नया रूप सामने आ रहा है। यह निधि का

दुरुपयोग है। गोगावले को डेढ़ सौ करोड़ की निधि दी गई है, यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मंत्री पद नहीं दिया इसलिए उन्हें शांत करने के लिए यह कीमत चुका रहे हैं क्या? 'महाराष्ट्र की राजनीति में निधि आवंटन एक शोध का विषय है', ऐसा राऊत ने कहा। 'लोग डर के मारे पार्टी छोड़ रहे हैं। जिन लोगों ने दल-बदल किया, उनका एक पैर जेल में था। चाहे वे शिवसेना के हों या एनसीपी के। एकनाथ शिंदे के पास मुख्यमंत्री बनने के लिए १४५ का आंकड़ा नहीं था। मुख्यमंत्री वे खुद नहीं बने, उन्हें किसी और ने बनाया। जिनके पास मुख्यमंत्री बनने का आंकड़ा है, वे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, दूसरे पर आंकड़ा लगा रहे हैं, ऐसा राऊत ने कहा।

जिन विधानसभा क्षेत्र को निधि नहीं दी गई है, वहां की जनता टैक्स नहीं जमा करती है क्या?

उन्हें विकास का अधिकार नहीं है क्या? - अंबादास दानवे

मुंबई : राज्य की गद्दार शिंदे सरकार की ओर से विधायकों को निधि आवंटन में किए गए पक्षपात को लेकर सोमवार को विधान परिषद में विपक्ष का आक्रामक रूप दिखाई दिया। विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। विधान परिषद के विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि निधि आवंटन में भेदभाव एक प्रकार से राज्य की जनता के साथ अन्याय है, ऐसे शब्दों में प्रतिपक्ष के नेता दानवे ने शिंदे सरकार से सवाल करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों को कुछ भी निधि नहीं दी है तो वहीं सत्तापक्ष के विधायकों को लगभग ५० करोड़ तक की निधि दी है, जबकि उपमुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि निधि वितरण में पक्षपात नहीं किया गया है।



सदन में नियम २८९ के तहत बोलते हुए दानवे ने कहा कि निधि के रूप में जो रकम वितरित की जा रही है, वह राज्य की जनता की जेब से जमा हुई है। जिन विधानसभा क्षेत्र को निधि नहीं दी गई है, वहां की जनता टैक्स नहीं जमा करती है क्या? उन्हें विकास का अधिकार नहीं है क्या? ऐसा सवाल भी दानवे ने किया। निधि वितरण में पक्षपात हुआ है कि नहीं, सरकार इस

मामले में स्पष्टीकरण दे। जिन्होंने वोट नहीं दिया है, उन्हें निधि नहीं देने की मंशा सरकार की नहीं है क्या? क्या वे लोग पाकिस्तान से आए हैं? निधि आवंटन में पक्षपात क्यों हो रहा है, जबकि सरकार के मंत्री ने आश्वस्त किया था कि निधि वितरण में कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बावजूद राज्य में निधि वितरण में पक्षपात का काम शुरू है।

गोल्ड ईटीएफ के प्रति फिर बढ़ा निवेशकों का आकर्षण, जून तिमाही में किया 298 करोड़ रुपए का निवेश

नई दिल्ली, एजेंसी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों (गोल्ड-ईटीएफ) में अप्रैल-जून की तिमाही में 298 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इससे पिछली लगातार तीन तिमाहियों के दौरान गोल्ड ईटीएफ से निकासी देखने को मिली थी। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सुरक्षित निवेश उत्पाद में निवेश करना जारी रखेंगे। हालांकि, यदि एक साल पहले की समान अवधि से तुलना की जाए, तो गोल्ड ईटीएफ में निवेश 80 प्रतिशत घट गया है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन तिमाही में गोल्ड ईटीएफ का परिसंपत्ति आधार और निवेशक खातों या फोलियो की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (2023-24) की अप्रैल-जून तिमाही में गोल्ड-ईटीएफ में 298 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इससे पहले मार्च तिमाही में गोल्ड ईटीएफ से 1,243 करोड़ रुपए, दिसंबर तिमाही में 320 करोड़ रुपए और सितंबर तिमाही में 165 करोड़ रुपए की निकासी देखने को मिली थी। वहीं जून, 2022 को समाप्त तिमाही में गोल्ड ईटीएफ में 1,438 करोड़ रुपए का निवेश आया था।

सैंकटम वेल्थ के प्रमुख-निवेश उत्पाद आलेख यादव ने कहा, "पिछली कुछ तिमाहियों में गोल्ड ईटीएफ से निकासी की



वजह दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को समाप्त करना और स्थानीय शेयर बाजारों की तुलना में सोने का प्रदर्शन कमजोर रहना है। मॉनिंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस श्रेणी में प्रवाह धीमा हो रहा है। इसका मुख्य कारण निवेशकों का शेयर जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले परिसंपत्ति वर्ग की ओर झुकाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही हैं, जो निवेशकों को किनारे पर रहने और निवेश के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

पिछले कुछ साल में अपने शानदार प्रदर्शन से सोने ने निवेशकों की काफी आकर्षित किया है और फोलियो संख्या में लगातार बढ़ती इसका प्रमाण है। गोल्ड ईटीएफ में फोलियो संख्या जून तिमाही में 1.5 लाख बढ़कर 47.52 लाख हो गई, जो एक साल पहले 46.06 लाख थी। इससे पता चलता है कि निवेशकों का झुकाव सोने से जुड़े कोषों की ओर बढ़ा है। इसके अलावा जून, 2023 में गोल्ड ईटीएफ के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) 10 प्रतिशत बढ़कर 22,340 करोड़ रुपए हो गईं, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 20,249 करोड़ रुपए थीं।

सोने की कीमतों में आई रिकॉर्ड गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने की कीमतों में आज रिकॉर्ड गिरावट आई है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। पिछले सप्ताह भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। गोल्ड की कीमतें अब गिरकर 59 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार को सोने के भाव लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। सुबह सोना गिरावट के साथ खुला है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें।

आज क्या हैं गोल्ड के भाव

एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार की सुबह 4 अगस्त 2023 को डिलीवरी वाला सोना 59172 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है। यह शुक्रवार की शाम को 59309 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। 5 अक्टूबर 2023 को डिलीवरी वाला सोना 59602 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है।



क्या है चांदी का भाव

चांदी की कीमतों भी सोमवार की सुबह गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोमवार की सुबह 5 सितंबर 2023 को डिलीवरी वाली चांदी का भाव 74800 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर खुला है। वहीं 5 दिसंबर 2023 को डिलीवरी वाली चांदी का भाव गिरावट के साथ 76345 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला है। सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.29 फीसदी या 5.80 डॉलर की गिरावट के साथ 1999.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सोने का वैश्विक हाजिर भाव भी गिरकर 1959.24 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

अप्रैल-जून में बिजली खपत 1.8 प्रतिशत बढ़कर 407.76 अरब यूनिट पर

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में बिजली की खपत चालू साल की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 1.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 407.76 अरब यूनिट पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मुख्य रूप से कारण बेमौसम बारिश और बिपरजॉय चक्रवात की वजह से बिजली खपत में वृद्धि मामूली रही है। इससे पिछले साल की अप्रैल-जून तिमाही में बिजली की खपत 400.44 अरब यूनिट (बीयू) थी और 2021 की समान अवधि में बिजली की खपत इससे पिछले साल की तुलना में 17.6 प्रतिशत अधिक रही थी।



पहले अनुमान लगाया था कि गर्मियों के दौरान देश में बिजली की मांग 229 गीगावॉट पर पहुंच जाएगी लेकिन बेमौसम बरसात, बिपरजॉय चक्रवात और भारी मानसूनी बारिश के कारण इस साल अप्रैल-जून में यह अनुमानित स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। मंत्रालय ने आपूर्ति बाधाओं के कारण होने वाली कटौती से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं। आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता पर परिचालन करने को कहा गया है। इसके अलावा इन संयंत्रों को किसी भी कमी से बचने के लिए मिश्रण के लिए कोयला आयात करने का भी निर्देश दिया गया है।

अप्रैल-जून, 2023 में अधिकतम पूरी की गई बिजली की मांग बढ़कर 223.23 गीगावॉट हो गई, जो 2022 की समान अवधि में 215.88 गीगावॉट थी। अप्रैल-जून, 2021 में यह 193.99 गीगावॉट थी। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिजली की अधिकतम मांग यानी एक दिन में अधिक बिजली की आपूर्ति में वृद्धि धीमी रही है। बिजली मंत्रालय ने

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण बिजली की मांग कम हो गई है, क्योंकि लोगों ने पिछले साल की तुलना में अप्रैल-जून, 2023 के दौरान ठंडक प्रदान करने वाले उपकरणों का कम इस्तेमाल किया।

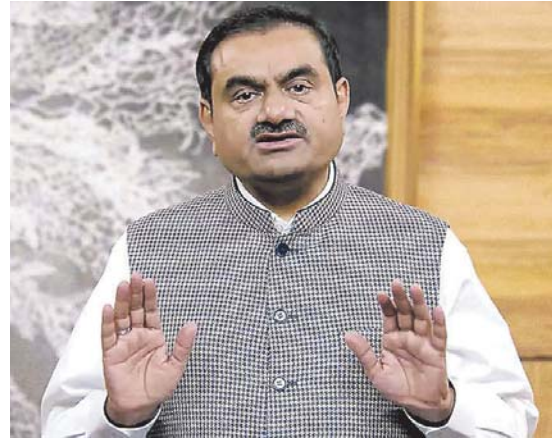
बिक गई अडानी की 1600 करोड़ की कंपनी, अमेरिकी फर्म ने खरीदी 90 प्रतिशत हिस्सेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी। अडानी समूह की दो कंपनियां बिक गई हैं। टॉप ग्लोबल इक्रीटी फर्म बेन कैपिटल ने अडानी समूह की कंपनी अडानी कैपिटल और अडानी हाउसिंग का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण को लेकर दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया है। इस डील के तहत बेन कैपिटल अडानी कैपिटल और अडानी हाउसिंग की 90 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर लेगी। जबकि 10 फीसदी हिस्सेदारी मैनेजमेंट, एमडी और सीईओ गौतम गुप्ता के पास रहेगी।

कितने में हुई डील

इस डील के बाद अडानी की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेन कैपिटल के पास पहुंच गई है। अमेरिकी फर्म ने 1440 करोड़ रुपये में यह हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं अडानी फाइनेंशियल सर्विस का कुल वैल्यूएशन 1600 करोड़ रुपये की है। इस डील के बार में गौतम अडानी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि बेन कैपिटल जैसे निवेशक कंपनी के साथ जुड़े हैं। वहीं बेन कैपिटल ने कहा कि उन्हें अडानी कैपिटल की क्षमता पर पूरा भरोसा है।

गौरतलब है कि साल 2017 में अडानी समूह ने अपना शैडो बैंकिंग बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अब अडानी परिवार इस कंपनी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहा है। बेन कैपिटल ने अडानी परिवार की सौ फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। जबकि गौरव गुप्ता अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखेंगे। वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर बने रहेंगे। अडानी समूह की इन दोनों कंपनियों में



अगले साल मार्च से परिचालन शुरू करेगी। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे आयात पर भारत की निर्भरता कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। तांबे को विद्युतीकरण की धातु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गहरे विद्युतीकरण के लिए तारों की जरूरत होती है। ये तार आमतौर पर तांबे से बने होते हैं। ऊर्जा बदलाव की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), चार्जिंग अवसंरचना, सौर फोटोवोल्टिक (पीवी), पवन ऊर्जा और बैटरी

हिस्सेदारी हासिल करने के बाद बेन कैपिटल इस कंपनी में 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी। कंपनी को आर्थिक मजबूती देने के लिए बेन कैपिटल नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर के तौर पर कंपनी को 5 करोड़ डॉलर का लिक्विडिटी लाइन भी उपलब्ध करवाएगी। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह अलग-अलग तरीके से फंड जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में अडानी समूह के कर्ज से लेकर कंपनी के वित्तीय सेहत पर सवाल उठे थे। इस रिपोर्ट के बाद से कंपनी कर्ज को लगातार कम करने की कोशिश में जुटी है। उधर अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह की गुजरात के मुंद्रा में स्थित तांबा फैक्ट्री

में तांबे की जरूरत होती है। समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की अनुष्णगी कच्छ कॉपर लिमिटेड (केसीएल) दो चरणों में प्रति वर्ष 10 लाख टन परिष्कृत तांबे के उत्पादन के लिए एक तांबा रिफाइनरी परियोजना स्थापित कर रही है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि केसीएल ने चरण-1 में पांच लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के लिए वित्तपोषण हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहला चरण वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले अडानी ने भी कंपनी की सालाना आमसभा में कहा था कि यह परियोजना अपने तय समय के अनुसार चल रही है।

‘इग्स लेने की वजह से गोरी है...’



‘देव डी’ और ‘ये जवानी है दीवानी’ जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस कल्कि केंकला के लिए सफलता का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लाइफ के मुश्किल

दौर के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोग उनके गौर होने का मजाक उड़ाते थे. साथ ही ये भी मानते थे कि वो इग्स लेने की वजह से इतनी गोरी हैं.

कल्कि ने हाल में एक शो ‘द मेल फेमिनिस्ट’ में सिद्धार्थ आलमबायन को दिए इंटरव्यू में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए. एक्ट्रेस ने कहा कि, उनके गौर रंग को देखकर लोग ये मानते थे कि वो इग्स लेती हैं. इतना ही नहीं रंग गौरा होने की वजह से मेरे करेक्टर पर भी बहुत सवाल उठते थे. क्योंकि लोगों का मानना था कि गौर रंग की लड़कियां कैरेक्टर लेस होती हैं. लेकिन जब मैं उनसे तमिल में बात कर लेती थी तो उनका नजरिया तुरंत बदल जाता है.

फिल्मों के बीच तुलना नहीं की जानी चाहिये : सनी देओल

सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता की फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि गदर रिलीज होने के 22 साल बाद अब गदर 2 पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म की रिलीज के साथ बिग स्क्रीन पर उसी दिन अक्षय कुमार की ओएमजी 2 भी रिलीज होने जा रही है। हाल ही में सनी देओल से गदर 2 और ओएमजी 2 के क्लैश के बारे में पूछा गया। जिसका उन्होंने जवाब दिया।



गदर ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई की थी, जबकि लगान ने बहुत कम कमाई की। सनी देओल कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग तुलना क्यों करते हैं। लेकिन गदर की धारणा वैसी नहीं थी, पर लोगों ने सोचा कि यह मसाला फिल्म है, और पुरानी टाइप की

पिक्चर है, इसमें पुराने टाइप के गाने हैं। दूसरी ओर, लोगों ने सोचा कि लगान क्लासिक फिल्म थी। लोगों ने गदर को उन्होंने पसंद किया। मुझे याद है कि एक अवॉर्ड शो में गदर का एक स्पूफ बनाया था, लेकिन हम इससे परेशान नहीं थे। यह मेरी कुछ अन्य फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल और दिल इनके बीच भी टक्कर हुई थी। जबकि दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है, लेकिन लोग तुलना करना पसंद करते हैं।

सनी देओल आगे कहते हैं, ‘मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि जो फिल्म ज्यादा अच्छी होती है फिर भी आप उसकी दूसरी फिल्मों के साथ तुलना करते हो। जिस चीज की बाराबरी नहीं है, उसकी तुलना मत करो। जिन फिल्मों की कोई तुलना नहीं है उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।’

योगा पर डाक्यूमेंट्री फिल्म 'योगिक विज्ञान'

कैवल्यधाम ने 'योगिक विज्ञान' नामक एक वृत्तचित्र के लॉन्च की घोषणा की। डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य योग के पीछे के विज्ञान पर प्रकाश डालकर योग का रहस्य उजागर करना है। फिल्म पिछले 100 वर्षों में योग के विकास को दर्शाती है और वैज्ञानिक प्रयोगों और मान्यताओं के माध्यम से धारणाओं और आम मिथकों को तोड़ती है। डॉक्यूमेंट्री का विमोचन महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सुरेश प्रभु, कैवल्यधाम शताब्दी समिति के अध्यक्ष, चांसलर ऋषिहुड विश्वविद्यालय और पूर्व कैबिनेट मंत्री जैसी प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। डॉक्यूमेंट्री में कैवल्यधाम के लगभग एक शताब्दी तक योग के क्षेत्र में किए गए मौलिक कार्य को भी दर्शाया गया है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला में सहाद्री पहाड़ों में स्थित इस संस्थान के विकास की आकर्षक कहानी बताता है। कैवल्यधाम को योग में वैज्ञानिक अनुसंधान करने और दुनिया का पहला योग कॉलेज स्थापित करने वाला दुनिया का पहला संस्थान होने का गौरव प्राप्त है। अपने पूरे इतिहास में, कैवल्यधाम ने वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित, अपने शुद्धतम पारंपरिक रूप में योग का प्रचार किया है।

टीवी से सिनेमा तक का सफर तय कर चुकीं कश्मीरा

25 जुलाई 1986 के दिन पुणे में जन्मी कश्मीरा ईरानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीवी की दुनिया से लेकर फिल्मों तक में वह अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं. हालांकि, उन्हें वह कामयाबी नसीब नहीं हुई, जिसकी वह तलबगार थीं. बर्थडे स्पेशल में हम आपको कश्मीरा की जिंदगी के चंद



किस्सों से रूबरू करा रहे हैं. कश्मीरा हमेशा से एक्टिंग की

दुनिया में कदम रखना चाहती थीं और फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश रखती थीं. हालांकि, उन्होंने अपने सपने की शुरुआत छोटे पर्दे से की. सबसे पहले उन्होंने सीरियल अंबर धरा से टीवी की दुनिया में कदम रखा. इस सीरियल में अंबर के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड भी मिला था.

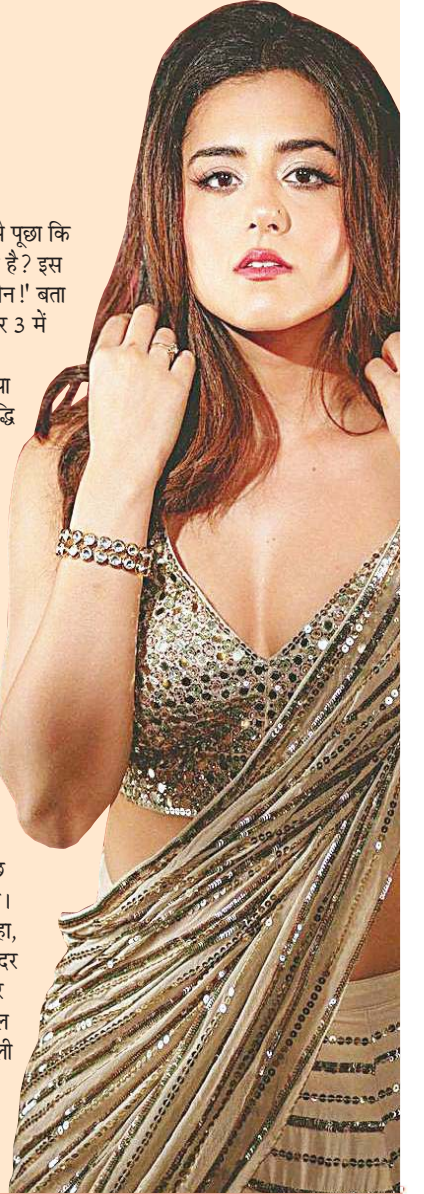
रिद्धि डोगरा ने बताई शाहरुख की खूबियां

रिद्धि डोगरा जल्द ही बहुचर्चित फिल्म जवान में नजर आएंगी। इस फिल्म में वह शाहरुख खान के साथ स्क्रीन साझा करेंगी, जिसे लेकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि बीते महीने जवान का प्रिव्यू रिलीज हुआ था, जो सोशल मीडिया पर जबर्दस्त हिट रहा। हाल ही में रिद्धि ने सोशल मीडिया पर फैंस से बातचीत का एक सेशन रखा। इस दौरान उन्होंने शाहरुख की दिल खोलकर तारीफ की। साथ ही सलमान खान का भी जिक्र किया। बता दें कि हाल ही में रिद्धि ने ट्विटर पर एक सेशन रखा, जहां यूजर्स ने उनसे काफी दिलचस्प सवाल पूछे। एक यूजर ने पूछा, शाहरुख के साथ काम करते हुए उनकी कौन सी खूबी आपको पसंद आई? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'सबकुछ। आमतौर पर जब आप अपने पसंदीदा लोगों से निजी रूप से मिलते हैं तो आपको निराशा होती है, क्योंकि वे भी आखिर इंसान हैं। लेकिन, शाहरुख खान के साथ ऐसा नहीं है। वह असाधारण व्यक्ति हैं। आप उनके बारे में जैसा पढ़ते और सुनते हैं, वह सच में वैसे ही हैं।'



बातचीत के दौरान एक अन्य यूजर ने रिद्धि से पूछा कि उन्हें सलमान खान की कौन सी फिल्म पसंद है? इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'हम आपके हैं कौन!' बता दें कि शाहरुख के अलावा रिद्धि फिल्म टाइगर 3 में सलमान के साथ भी नजर आएंगी।

एक अन्य मीडिया इंटरव्यू में भी रिद्धि ने शाहरुख और सलमान खान के साथ काम करने का अनुभव साझा करते हुए खुलासा किया कि दोनों सितारों के साथ काम करना एक लर्निंग सेशन जैसा था। बतौर कलाकार उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। रिद्धि ने आगे कहा, 'मैंने दोनों के अंदर बच्चों जैसी एनर्जी देखी। वह अपने काम और बाकी चीजों में इस एनर्जी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं।' बात फिल्म जवान की करें तो एटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान और रिद्धि के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति भी अहम रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म सात सितंबर को रिलीज होगी।



'बचपन का प्यार' में राजकुमार-वाणी!

बॉलीवुड फिल्मकार अनुभव सिन्हा, अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री वाणी कपूर को लेकर फिल्म बचपन का प्यार बनाने जा रहे हैं। अनुभव सिन्हा, राजकुमार राव और वाणी कपूर को लेकर फिल्म बचपन का प्यार बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की कहानी लखनऊ शहर में सेट होगी। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी अपूर्व धर बडगैयों को दी गई है। कहा जा रहा है कि अगले महीने से राजकुमार और वाणी फिल्म की शूटिंग आरंभ करेंगे।



यह पहली बार होगा, जब वाणी, अनुभव के बैनर तले काम करेंगी, जबकि राजकुमार इससे पहले अनुभव के निर्देशन में बनी फिल्म भीड़ में काम कर चुके हैं। इस फिल्म को बनाने से पहले अनुभव नेटफिलक्स की हाइजैक ड्रामा सीरीज आईसी 814 पर काम खत्म कर लेना चाहते हैं। इस सीरीज में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह समेत कई कलाकार होंगे।